Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत् विकास

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: JHPM18

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत् विकास

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 87501 87501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

JPSC DLP विषय सूची (Contents)

1. अर्थव्यवस्था : एक परिचय		**7–22**
1.1	अर्थशास्त्र क्या है?	7
1.2	अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र में संबंध	7
1.3	अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएँ	8
1.4	अर्थव्यवस्था के प्रकार	9
1.5	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	11
1.6	उत्पादन के कारक	13
1.7	आय का चक्रीय प्रवाह	14
1.8	भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एवं समस्याएँ	17
1.9	कुछ महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट	17
2. राष्ट्रीय आय		**23–34**
2.1	राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ एवं अंतर्संबंध	23
2.2	घरेलू आय एवं राष्ट्रीय आय	27
2.3	राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ	28
2.4	राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक	29
2.5	कारक आय बनाम हस्तांतरण आय	31
2.6	राष्ट्रीय आय मापन की सीमाएँ	32
2.7	राष्ट्रीय आय मापन में हाल में किये गए परिवर्तन	32
3. मुद्रास्फीति		**35–55**
3.1	मुद्रास्फीति के कारण	35
3.2	मुद्रास्फीति के प्रकार	36
3.3	फिलिप्स वक्र	38
3.4	व्यापार चक्र	38
3.5	आधार प्रभाव एवं मुद्रास्फीति की गणना	39
3.6	कीमत सूचकांक विधि	40
3.7	भारत में ऊँची मुद्रास्फीति के कारण	46

3.8	मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण	48
3.9	मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव	48
3.10	मुद्रास्फीति नियंत्रण के संदर्भ में उपाय एवं नीतियाँ	50
3.11	भारत में मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति	50
3.12	मुद्रास्फीति से संबंधी शब्दावली	52
4. जनसांख्यिकीय विशेषताएँ		**56–83**
4.1	जनांकिकी अवधारणा	56
4.2	जनसंख्या संबंधित सिद्धांत	58
4.3	कार्यशील जनसंख्या एवं जनांकिकीय लाभांश	60
4.4	जनसंख्या पिरामिड	60
4.5	जनसंख्या से संबंधित पारिभाषिक शब्द	61
4.6	भारत की जनसंख्या नीति	64
4.7	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000	64
4.8	भारत में जनगणना	65
4.9	सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना, 2011	65
4.10	भारत की जनगणना, 2011 के प्रमुख आँकड़े	66
4.11	श्रम क्या है?	70
4.12	श्रम सुधार के लिये सरकार के प्रयास	72
4.13	मज़दूरी संहिता, 2019	74
4.14	श्रमिकों से संबंधित महत्त्वपूर्ण योजनाएँ	76
4.15	शब्दावली	80
5. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था		**84–114**
5.1	भारत में कृषि विकास : उत्पादन तथा उत्पादकता	89
5.2	निम्न उत्पादकता के कारण	92
5.3	कृषि उत्पादकता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा लिये गए कदम	93
5.4	हरित क्रांति	98
5.5	राष्ट्रीय कृषि नीति	100
5.6	विश्व व्यापार संगठन और कृषि	101
5.7	कृषि आगतों और उत्पादन का बाज़ारीकरण और मूल्यीकरण	103
5.8	सहकारी कृषि	110
5.9	कृषि गणना 2015-16	112

6. लोक वित्त **115–165**

6.1 लोक वित्त की विषय-सामग्री 115

6.2 लोक वित्त एवं निजी वित्त 116

6.3 कर 118

6.4 भारतीय कर व्यवस्था 123

6.5 प्रत्यक्ष कर 124

6.6 अप्रत्यक्ष कर 130

6.7 मूल्य-वर्द्धित कर 131

6.8 कर सुधार 133

6.9 वस्तु एवं सेवा कर 137

6.10 राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण 156

6.11 रिवर्स चार्ज 157

6.12 कर प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट 157

6.13 शब्दावली 158

7. सार्वजनिक व्यय **166–170**

7.1 सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत 166

7.2 सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण 167

7.3 सार्वजनिक व्यय का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 168

7.4 सार्वजनिक व्यय : आंतरिक व बाह्य उधारियाँ 169

8. बजट **171–190**

8.1 बजट निर्माण प्रक्रिया 171

8.2 घाटे के बजट की विभिन्न अवधारणाएँ/प्रकार 178

8.3 घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन 184

8.4 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 185

8.5 वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग: एफआरएमडी 189

9. राजकोषीय नीति **191–198**

9.1 राजकोषीय नीति के उद्देश्य 191

9.2 रोज़गार प्राप्ति में राजकोषीय नीति की भूमिका 192

9.3 स्थायित्व और आर्थिक विकास 193

9.4	केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध	194
9.5	केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध: वित्त आयोग की भूमिका	196
9.6	73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के वित्तीय पहलू	196
10. भारतीय मौद्रिक नीति तथा भारत में बैंकिंग व्यवस्था की संरचना		**199–268**
10.1	वित्तीय प्रणाली	199
10.2	मुद्रा बाज़ार	203
10.3	बैंकिंग	**213**
10.4	केंद्रीय बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक	218
10.5	मौद्रिक नीति	231
10.6	बेसल मानक	238
10.7	अन्य बैंकिंग संस्थाएँ	239
10.8	भारत में बैंकों का विलय	248
10.9	आधार दर और सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर	252
10.10	डॉ. जनक राज पैनल	254
10.11	प्राथमिक क्षेत्र उधार	255
10.12	अनिवासी भारतीय जमा खाता	256
10.13	बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	256
10.14	IFSCs प्राधिकरण विधेयक, 2019	257
10.15	बैंकिंग शब्दावली	258
11. भारत के व्यापार की संरचना		**269–320**
11.1	भुगतान संतुलन	269
11.2	विदेशी विनिमय दर	283
11.3	फेरा और फेमा	287
11.4	मुद्रा का मूल्यह्रास	288
11.5	मुद्रा का अवमूल्यन	289
11.6	मुद्रा की परिवर्तनीयता	291
11.7	विदेशी व्यापार	295
11.8	क्षेत्रीय व्यापार समझौते	308
11.9	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी	316
11.10	अर्थव्यवस्था की वृद्धि में विदेशी पूंजी और तकनीकी की भूमिका	318

अध्याय
1

अर्थव्यवस्था : एक परिचय (Economy : An Introduction)

किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (Socio-economic Conditions) में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों (Available Resources) का समुचित नियोजन (Appropriate Planning) करते हुए अर्थ (Money) को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। वास्तव में 'अर्थव्यवस्था' शब्द अधूरा ही रहेगा जब तक कि इसके आगे किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए, जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था इत्यादि। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र (Economics) का गतिशील (Dynamic) चित्र है जो किसी विशेष अवधि तक ही सीमित होता है। यदि हम कहते हैं- 'समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था' तो इसका तात्पर्य होता है- वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन।

1.1 अर्थशास्त्र क्या है? *(What is Economics?)*

अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके।

एक व्यक्ति के स्तर (व्यष्टि स्तर) पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर (समष्टि स्तर) पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, इसलिये संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है, जैसे- व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिये लोककल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है।

अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात् "अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।"

सामान्य शब्दों में, "अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।" प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' (The Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

1.2 अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र में संबंध *(Relation between Economy and Economics)*

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।
- जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे 'अर्थव्यवस्था' कहते हैं।
- 'कीमत सिद्धांत' व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत, पूर्ति तथा मांग शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।
- विकसित देशों का समूह, जहाँ प्रशासित कीमत क्रियाविधि अपनाई जाती है, दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं।
- नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन्हें प्राथमिक वस्तुएँ कहते हैं।
- मानव शरीर या मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति को श्रम कहते हैं।
- पूंजी का आशय ऐसे मानव निर्मित संसाधनों से है जिनका इस्तेमाल उत्पादन में किया जाता है।
- भारत में कृषि/खाद्य उत्पादों के लिये एक प्रमाणचिह्न के रूप में एगमार्क (AGMARK) का प्रयोग किया जाता है।
- भारत में मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिये अनिवार्य मानक चिह्न भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) है।
- घरेलू क्षेत्रों को विशुद्ध उदारदाता माना जाता है। इसका कारण वैयक्तिक बचतें हैं-ये घरेलू क्षेत्र की आय और उपयोग का अंतर होती हैं।
- ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, 2019 का मुख्य विषय 'The Challenge of Hunger and Climate Change' है।
- विश्व विकास रिपोर्ट, 2019 की थीम 'कार्य के बदलते स्वरूप' है।
- कारोबार सुगमता सूचकांक, 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है एवं इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर न्यूज़ीलैंड है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम समान्य नियंत्रण रखना।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है:
6th JPSC (Mains)
(a) विदेश में व्यावसायिक इकाइयाँ स्थापित करना।
(b) आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम का परित्याग।
(c) अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना।
(d) विदेशी ऋण में वृद्धि लाना।

2. भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है?
4th JPSC (Pre)
(a) समाजवादी (b) मिश्रित
(c) गांधीवादी (d) स्वतंत्र

3. उत्पादन के निम्नलिखित कारकों में से किसमें 'जोखिम' की अवधारणा निहित है?
(a) भूमि
(b) पूंजी
(c) श्रम
(d) उद्यमशीलता

4. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प 'संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएँ' (Transitional economics) हैं?
(a) पहली दुनिया के देश (b) दूसरी दुनिया के देश
(c) तीसरी दुनिया के देश (d) चौथी दुनिया के देश

5. आभूषण (Jewellery) उदाहरण है:
(a) भौतिक पूंजी का
(b) वित्तीय पूंजी का
(c) बौद्धिक पूंजी का
(d) कलात्मक बौद्धिक पूंजी का

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. वैज्ञानिक पूंजी या प्रौद्योगिकी पूंजी के स्वामित्व को पेटेंट (Patent) कहा जाता है।
2. व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को कॉपीराइट (Copyright) कहा जाता है।
3. कलात्मक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क (Trade Mark) कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से असत्य हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

7. नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को कहते हैं:
(a) प्राथमिक क्षेत्र (b) द्वितीयक क्षेत्र
(c) तृतीयक क्षेत्र (d) चतुर्थक क्षेत्र

8. निम्नलिखित में से द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है:
(a) विनिर्माण
(b) निर्माण
(c) खनन एवं उत्खनन
(d) जल विद्युत एवं गैस आपूर्ति

9. समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है:
(a) योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण।
(b) श्रम-विभाजन और विनिमय।
(c) सरकार अंतिम निर्णायक के रूप में।
(d) निजी स्वामित्व की धारणा नहीं।

उत्तरमाला

1. (c) 2. (b) 3. (d) 4. (b) 5. (b) 6. (b) 7. (b) 8. (c) 9. (b)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिये। **3rd JPSC (Mains)**
2. अर्थव्यवस्था क्या है? इसके आर्थिक क्रिया एवं प्रकारों को समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित करते हुए इसका विश्लेषण करें।
3. उत्पादन के कारकों व क्षेत्रों को स्पष्ट करते हुए यह स्पष्ट करें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्यों महत्त्वपूर्ण है?
4. आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? इसके द्वारा हमारी वित्तीय व्यवस्था कैसे प्रभावित होती है? स्पष्ट करें।

अध्याय
2

राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय आय का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से होता है-

- अर्थव्यवस्था के आकार तथा आर्थिक निष्पादन के स्तर की माप में।
- पछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के विकास की प्रवृत्ति या गति का पता लगाने में।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं उनमें आवधिक परिवर्तनों के सापेक्ष राष्ट्रीय आय के संयोजन और संरचना का पता लगाने में।
- भविष्य में अर्थव्यवस्था के विकास की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने में।
- विकास दर में वृद्धि के लिये सरकार द्वारा बनाई जाने वाली उपयुक्त नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण में मदद देने में।
- व्यवसायियों को भविष्य में अपने उत्पादों की मांग से संबंधित अनुमान लगाने में।
- पिछले प्रदर्शन के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भविष्य के लक्ष्य तय करने में।
- वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में तुलनात्मक अध्ययन में।

2.1 राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ एवं अंतर्संबंध *(Various Concepts Related to National Income and Inter-relationship)*

बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद *(Gross Domestic Product at Market Price–GDP_{MP})*

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर-निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाज़ार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्द्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

- भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- यहाँ देश की घरेलू अर्थात् आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतर्गत जलक्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंत:क्षेत्र, जैसे-दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं।
- राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये, एक किसान द्वारा ₹1000 का कपास उत्पादित किया गया। इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसका धागा बनाया जाता है एवं इसके धागे को ₹2000 में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके इसका कपड़ा बनाकर ₹3000 में बेच दिया जाता है एवं अंत में एक रेडीमेड शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बनाकर ₹4000 में बेच देती है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल ₹4000 को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य एवं दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है।

बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(Gross National Product at Market Price– GNP_{MP})*

बाज़ार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात् देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाज़ार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्द्धन का योग है या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।

अध्याय
3

मुद्रास्फीति (Inflation)

'मुद्रास्फीति' से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह 'मुद्रास्फीति की अवस्था' कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमज़ोर होना ही मुद्रास्फीति की अवस्था है। मुद्रास्फीति के कारण आगतों की कीमत तथा ब्याज दर में वृद्धि होती है, जिस कारण निवेश की लागत में भी वृद्धि होती है, जो कि संवृद्धि की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में जानी जाती है।

जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है अर्थात् वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत् रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे 'मुद्रास्फीति' कहा जाता है। यह व्यापार चक्र का एक भाग है। अस्थायी तथा छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। मुद्रास्फीति को हमेशा बुरा नहीं माना जाता। मंदी के दौरान सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी को स्फीतिकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके परिणाम अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक नहीं होते हैं।

वस्तु की मांग ↑ + वस्तु की आपूर्ति ↓ ⇒ वस्तु की कीमत ↑ (मुद्रास्फीति)

विकास दर एवं मुद्रास्फीति के बीच एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि यदि विकास दर बढ़ानी है तो इसके लिये अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिये निवेश को बढ़ाना होगा। चूँकि निवेश एवं ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध होता है, इसलिये निवेश तभी बढ़ेगा जब ब्याज दर को घटाया जाए, परंतु यदि ब्याज दर बढ़ती है तो निवेश एवं विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति की ऊँची दर होने के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दर को बढ़ाना नहीं चाहता।

3.1 मुद्रास्फीति के कारण *(Causes of Inflation)*

मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति *(Demand-Pull Inflation)*

जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है तो उसे 'मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति' कहते हैं। मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से आ सकती है- लोगों की आय बढ़ने, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि कारणों से मांग बढ़ने से।

लागतजनित मुद्रास्फीति *(Cost-Push Inflation)*

यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे 'लागतजनित मुद्रास्फीति' कहते हैं। उत्पादन की बढ़ती लागत बहुमूल्य आगतों से संबंधित हो सकती है। यह प्राकृतिक कारणों, जैसे- बाढ़, सूखा या मानवीय कारणों, हड़ताल व तालाबंदी के कारण भी हो सकती है। मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक कर, परोक्ष कर में वृद्धि, स्टील, सीमेंट, रेलवे, कोयला एवं विद्युत इत्यादि के मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि करते हैं।

वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति *(Inflation by Global Causes)*

वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। किसी देश में मंदी की स्थिति में उसका निर्यात घटने से उसके साझेदार देश में आयातों में प्रत्यक्षत: कमी आती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

अध्याय
4

जनसांख्यिकीय विशेषताएँ (Demographic Features)

अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को श्रमबल के संसाधन के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा श्रम बल की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये श्रमबल को अन्य संसाधनों की उपस्थिति में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या किसी क्षेत्र-विशेष से जुड़ी एक परिकल्पना है, जिसमें समाज के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित भूभाग (गाँव, शहर, ज़िला, राज्य, देश या महाद्वीप) में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही 'जनसंख्या' कहलाती है।

नोट: भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग निवासित है।

- 11 जुलाई, 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के बिंदु को पार कर गई। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिये जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। अत: प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।

4.1 जनांकिकी अवधारणा *(Concept of Demographic)*

भारत की जनांकिकीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- अधिक जनसंख्या
- ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता
- उच्च वृद्धि दर
- निम्न लिंगानुपात
- आत्मनिर्भरता की स्थिति
- नृजातीय विविधता
- वृद्धि के परिणाम

अधिक जनसंख्या *(Excess population)*

किसी देश में अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो उसके अधिकतम (संपूर्ण) संसाधनों का अधिकतम दोहन कर सकने वाली न्यूनतम जनसंख्या हो। इस दृष्टि से भारत की स्थिति के संबंध में यह माना गया है कि यद्यपि अभी तक हमने संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं किया है, किंतु उनकी तुलना में जनसंख्या की अधिकता निर्विवादित रूप से प्राप्त कर ली है। दुनिया भर के क्षेत्रफल व व्यापार में भारत का जितना हिस्सा है उससे कई गुना अधिक हिस्सा जनसंख्या का है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2025-50 के बीच भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी क्योंकि चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 1% पर सीमित हो गई है जबकि भारत की 2011 में औसत वार्षिक जनसंख्या दर 1.64% है। ऐसी स्थिति में भारत की जनसंख्या 34 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी जबकि चीन की 60 वर्षों में दोगुनी होगी। जनसंख्या की अधिकता से आने वाले वर्षों में भीड़-भाड़, अपराध, महँगाई, आवास आदि की समस्याएँ तेज़ी से बढ़ सकती हैं।

देश में जनसंख्या अधिक होने के कारण निम्नलिखित हैं-

- मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर का अधिक होना।
- प्राय: कम उम्र में विवाह करने की सामाजिक मान्यता।

अध्याय
5

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Agriculture & Rural Economy)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किये जाते थे। उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था, लेकिन इसके पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है।

भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कृषि का महत्त्व इस बात में परिलक्षित होता है कि दुनिया के मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्र और 4.2 प्रतिशत पानी से हम विश्व की लगभग 17.5 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करने में कामयाब हैं। आज भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है एवं यह निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाला अकेला व्यवसाय है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं।

अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्त्व *(Importance of Agriculture in Indian Economy)*

अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 51 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में यह 14.2 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई शृंखला (आधार वर्ष 2011–12) के आधार पर 2018–19 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में योगदान 14.39 प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य संवर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 275.11 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर 285.21 मिलियन टन हो गया है। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों, चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अध्याय
6

लोक वित्त (Public Finance)

लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय-व्यय का अध्ययन करती है अर्थात् लोक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के आय एवं व्यय से होता है। लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोक वित्त को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है।

डॉ. डाल्टन के अनुसार, "लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक सत्ताओं के आय-व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है।

प्रो. सी.एल. बैस्टेल के अनुसार, 'लोकवित्त राज्य की लोकसत्ताओं के आय-व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। समग्रता से लोक वित्त मूल रूप से सरकारों के आय-व्यय से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों से है। वर्तमान में लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, इसके अंतर्गत सरकार के आय-व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है।

6.1 लोक वित्त की विषय-सामग्री *(Subject Matter of Public Finance)*

लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं की विवेचना इतिहास में भी मिलती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nation' (1776) के खंड 5 में लोक वित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। इस खंड में तीन अध्याय हैं जो क्रमशः सरकार के व्यय, सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण का विवेचन करते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्त व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है और अंततः इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

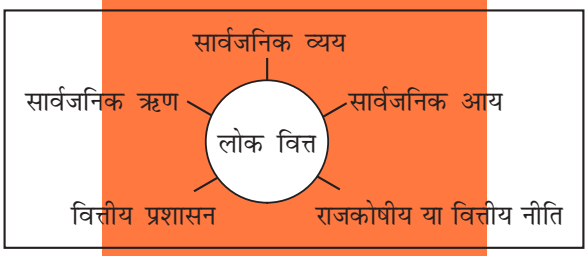

1. **सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure):** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन-किन मदों पर करना आवश्यक है? सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो? सार्वजनिक व्यय करते समय किन-किन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाए?

   सार्वजनिक प्राधिकरणों, यथा- केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किये जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। भारत में 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक व्यय तथा गैर-विकासात्मक व्यय के रूप में बाँटा जाता था, परंतु अब 1987-88 से कुल सार्वजनिक व्यय को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा रहा है-

   - योजनागत व्यय या आयोजन व्यय
   - गैर-योजनागत व्यय या आयोजन भिन्न व्यय।

नोटः अब इसको (गैर-योजनागत व्यय) भी समाप्त कर दिया गया है। अब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है।

अध्याय
7

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

सार्वजनिक व्यय से सामान्य तात्पर्य है सरकार के द्वारा वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आधारभूत अवसंरचना, रोज़गार, कृषि, तकनीकी उन्नयन आदि पर किया जाने वाला खर्च। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों के द्वारा किये जाने वाले समस्त प्रशासनिक, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिये किये जाने वाले व्यय शमिल होते हैं।

सार्वजनिक व्यय से सरकार के द्वारा न केवल जनता व राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है वरन् भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है, इसी कारण सार्वजनिक व्यय के द्वारा सरकार सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के परंपरागत उद्देश्यों के साथ ही सतत विकास और समावेशी विकास के उद्देश्यों को भी सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत शामिल करती जा रही हैं।

बजट 2020–2021 के अनुसार 2019–20 में कुल व्यय (संशोधित) 26,98,552 करोड़ रुपया है जबकि इस व्यय के 2020–2021 में बढ़कर 30,42,000 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है।

7.1 सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत *(Principles of Public Expenditure)*

सार्वजनिक व्यय का स्वरूप किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे- भारत में आतंकवाद, सीमायी चुनौतियों के मद्देनज़र सैन्य व्यय की आवश्यकता अधिक होगी, वहीं पर स्वीटज़रलैंड में यह समस्या कम होने के कारण सार्वजनिक व्यय में सैन्य क्षेत्र का हिस्सा कम होगा।

किंतु सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सकता है। वे निम्नलिखित हैं-

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत

- वर्तमान समय में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारें हैं और इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करेंगी। इसी प्रकार इनसे यह अपेक्षा है कि ये सभी क्षेत्रों, वर्गों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।
- सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में भी यही उपर्युक्त बात सत्य है। अत: सार्वजनिक व्यय से 'अधिकतम लोगों का अधिकतम' सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित होना चाहिये। यदि सार्वजनिक व्यय से किसी विशेष वर्ग, लिंग, क्षेत्र को ही केवल लाभ मिलता है तो इसे सही नहीं माना जाता है। अर्थात् इस सिद्धांत से तात्पर्य है 'अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण'।

अर्थव्यवस्था का सिद्धांत

सार्वजनिक व्यय का ध्येय दोहराव और अतिरेक खर्च को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिये ताकि राष्ट्रीय आय, प्रतिव्यक्ति आय और समस्त अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके।

स्वीकृति का सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय कितना हो, किस क्षेत्रक में हो; इसके लिये एक निर्धारित प्राधिकरण और प्राधिकारी होना चाहिये। इससे अपव्यय, दुहराव आदि समस्याओं से बचा जा सकता है; साथ ही अंकेक्षण (ऑडिट) और ज़िम्मेदारी निर्धारित करना भी आसान होगा।

अध्याय
8

बजट (Budget)

बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिये आवंटित करने की एक प्रक्रिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। इस 'वार्षिक वित्तीय विवरण' को ही 'आम बजट' कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

- सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्त्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं करेतर अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है।
- 1920–21 के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री **विलियम एकवर्थ** की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि रेलवे एक उद्यम है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकता है।
- भारत में पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- केंद्रीय बजट में तीन लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं–
  - आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान
  - चालू वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित अनुमान
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय

बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की संवृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है।

8.1 बजट निर्माण प्रक्रिया *(Budget Making Procedure)*

- बजट निर्माण प्रक्रिया वित्त मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों, नीति आयोग तथा शासकीय व्यय से जुड़े अन्य पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श से शुरू होती है।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिविज़न बजट बनाने से जुड़ी नोडल इकाई है।
- सामान्यत: प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितंबर माह में बजट डिविज़न सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं, विभागों और सुरक्षा बलों को एक सर्कुलर जारी करता है। पूरे वित्त वर्ष में होने वाले कुल व्यय का आकलन करने के इस सर्कुलर के ज़रिये सबकी मांगों को प्राप्त किया जाता है।
- सबकी मांगें प्राप्त हो जाने के उपरांत वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर, मंत्रालयों एवं विभागों के साथ गहन-विचार विमर्श करता है।
- इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तथा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसानों, व्यापारियों, उद्योगों से जुड़े लोगों, बुद्धिजीवियों से उनकी राय लेता है।

अध्याय
9

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं पर लगे कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

9.1 राजकोषीय नीति के उद्देश्य *(Purpose of Fiscal Policy)*

1. **संसाधनों को गतिशील करना (Mobilisation of Resources):** राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकारें राजकोषीय नीति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने का प्रयास करती हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों, सार्वजनिक बचत, निजी बचत आदि माध्यमों से सरकारें वित्तीय संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करती हैं।
2. **आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी (Reduction in Inequality of Income and Wealth):** राजकोषीय नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय और संपत्ति की असमानताओं को समाप्त कर समानता या सामाजिक न्याय को प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा उच्च आय वर्ग से आय कर की वसूली तथा कर राजस्व का गरीबी निवारण एवं अन्य समाज सुधार योजनाओं पर अधिक खर्च करने जैसे उपाय किये जाते हैं।
3. **मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण (Price Stability and Control of Inflation):** राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य घरेलू बाज़ार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को स्थिर रखना तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। इस हेतु सरकार वित्तीय घाटे को कम करने, कर बचत योजनाओं तथा वित्तीय संसाधनों के उत्पादक उपयोग को बढ़ाने का प्रयास करती है।
4. **रोज़गार सृजन (Employment Generation):** प्रभावशाली राजकोषीय नीति द्वारा सरकार रोज़गार सृजन का हर संभव प्रयास करती है। इसके लिये सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, छोटे उद्योगों को कर तथा शुल्क में राहत देने जैसे उपाय किये जाते हैं।

अध्याय
10

भारतीय मौद्रिक नीति तथा भारत में बैंकिंग व्यवस्था की संरचना (Indian Monetary Policy and Structure of Banking System in India)

एक बड़ी अर्थव्यवस्था को अपनी आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिये एक कुशल बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा उनके बैंकों द्वारा पूरी तरह से समर्थन/सहयोग प्रदान किया गया है। अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का सहयोग है। जहाँ तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जो कि हमारी बैंकिंग प्रणाली में प्रभाविता रखते हैं, को और दक्ष होना ज़रूरी है।

1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद के 50 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की बाज़ार संरचना विकसित हुई है। मार्च 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जमा राशि ₹ 80 लाख करोड़ थी; सरकारी बॉण्ड में ₹ 20 लाख करोड़ और उनके द्वारा ₹ 58 लाख करोड़ का ऋण और अग्रिम प्रदान किया गया। यह इस बात को दर्शाता है कि यह भारत में परिचालित समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल राशि का 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के बीच की राशि है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बाज़ार में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी तो है ही, इसके साथ इनका महत्त्वपूर्ण पदचिह्न भी मौजूद है, जो 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद 91 प्रतिशत से कुछ कम हो गया है। बाज़ार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर में गिरावट का मुख्य कारण उन 'नए निजी बैंकों' (एनपीबी) का आगमन रहा है, जिन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में लाइसेंस प्रदान करने के नियमों, के उदारीकरण के बाद, लाइसेंस प्रदान किये गए थे।

10.1 वित्तीय प्रणाली *(Financial System)*

वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वित्तीय संस्थाओं, व्यक्तियों, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों एवं सरकार द्वारा वित्त की मांग की जाती है तथा इसकी पूर्ति भी की जाती है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो पहलू हैं- 1. मांग 2. पूर्ति। मांग व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियों और सरकार आदि द्वारा की जाती है, जबकि पूर्ति बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है।

वित्त क्या है? *(What is Finance?)*

मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहा जाता है। इससे संबद्ध दो प्रमुख पारिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं-

- **वित्तीय विनिमय (Financial Exchange):** ऋण लेने एवं ऋण देने की क्रियाओं को वित्तीय विनिमय कहा जाता है।
- **वित्तीय बाज़ार (Financial Market):** एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, वित्तीय बाज़ार कहलाती है।

वित्तीय व्यवस्था का महत्त्व *(Importance of Financial System)*

वित्तीय व्यवस्था का महत्त्व निम्नलिखित है

- वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध सभी भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिकतम, मितव्ययी और कुशलतम उपयोग करके लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है।
- वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से ही उत्पादन के तत्त्वों, सामग्री, मशीन, बाज़ार, श्रम और पूंजी की उपलब्धता संभव हो पाती है।
- वित्तीय व्यवस्था द्वारा यह संभव हो पाता है कि धन का उपयोग कहाँ और कितनी मात्रा में किया जाए।
- लाभांश के रूप में अंशधारकों को कितनी मात्रा में धन का भुगतान किया जाए और कितनी राशि व्यवसाय के लिये रखी जाए।
- वित्तीय व्यवस्था द्वारा कोषों की व्यवस्था एवं उसकी वृद्धि कहाँ से और कितनी मात्रा में की जाए, इसका प्रबंध करती है।

अध्याय
11

भारत के व्यापार की संरचना (Trade Structure of India)

भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019–20 की प्रथम छमाही में भुगतान शेष की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्थिरता प्राप्त हुई है। भारत का विदेशी रिजर्व 10 जनवरी 2020 को 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई। भुगतान संतुलन में यह सुधार चालू खाता घाटा (सीएडी) के सिमित होने के कारण 2018–19 में यह 2.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019–20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया है। ऐसा चालू खाता घाटे में कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण हुआ है। निर्यात वृद्धि सेवा क्षेत्र में लचीलेपन के बावजूद वैश्विक निवेश, आउटपुट में मंदी तथा अत्यधिक व्यापार तनाव के कारण बाह्य मांग में कमी होने से कमज़ोर बनी हुई है। भुगतान संतुलन में सुधार के लिये वैदेशिक वित्तीय दशाओं में राहत, एफडीआई में प्रभावी वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों की पुनः सुदृढ़ता तथा घनप्रेषणों की बड़ी प्राप्तियों का भी योगदान है। वर्ष 2019–20 में निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह भी उत्साहवर्द्धन रहे हैं जिनसे प्रथम आठ महीनों में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई है, जो कि वर्ष 2018 – 19 की संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है।

सितंबर 2019 के अंत में यथास्थिति, विदेशी ऋण, जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2018–19 की तुलना में जीडीपी अनुपात की दृष्टि से भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2014–19 की अवधि में 7.5 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लगभग साथ-साथ, भारत की 'भुगतान शेष' स्थिति में सुधार हुआ है। यह सुधार वित्तीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति तक संचित विदेशी रिज़र्व के 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँचने के कारण हुआ है जो कि 2013–14 के अंत तक केवल 304.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत जैसी खुली व बढ़ती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिये 'भुगतान संतुलन' की स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

11.1 भुगतान संतुलन *(Balance of Payment)*

भुगतान संतुलन खाते की अवधारणा

भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन (Monetary Transactions) का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इस लेन-देन में उस देश की वस्तुओं, सेवाओं एवं वित्तीय पूंजी का आयात-निर्यात तथा वित्तीय हस्तांतरण हेतु भुगतान शामिल होते हैं।

- 'भुगतान संतुलन' का अर्थ है-एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन-देन, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा आय का लेन-देन शामिल होता है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात (दृश्य मदें), सेवाओं के निर्यात एवं आयात (अदृश्य मदें), वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे-स्टॉक्स, बॉण्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय, वास्तविक परिसंपत्तियों, जैसे-प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह लेन-देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' कहते हैं। किंडलबर्गर के शब्दों में, "एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के बीच में किये गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है।" इसके दो पक्ष होते हैं- 1. क्रेडिट साइड, 2. डेबिट साइड।
- क्रेडिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जबकि डेबिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। भुगतान संतुलन खाता में दिखाई जाने वाली मदों को दो भागों में बाँटा गया है-

1. दृश्य मदें (Visible Items)

इसके तहत भौतिक वस्तुओं के आयात-निर्यात को भुगतान संतुलन खाते में वस्तु खाता (Goods A/c) के तहत दिखाया जाता है। सामान्य तौर पर किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ वस्तु खाते से लगाया जाता है अर्थात् किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ दृश्य मदों के आयात एवं निर्यात से होता है और इन दृश्य मदों के आयात-निर्यात का अंतर 'व्यापार संतुलन' (Balance of Trade) कहलाता है।